मध्यप्रदेश में जल गंगा अभियान के पुरस्कार और परफार्मर की रैंकिंग जारी

खंडवा प्रथम, रायसेन द्वितीय और बालाघाट तृतीय स्थान पर

सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल

जल गंगा संवर्धन अभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले खंडवा जिले ने प्रथम स्थान, रायसेन ने द्वितीय और बालाघाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जिला व जनपद स्तरीय पुरस्कार की सूची जारी की है। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों की रैंकिंग सूची में जल गंगा संवर्धन अभियान में खंडवा जिले ने 92.50 प्रतिशत, रायसेन जिले ने 92.35 प्रतिशत और बालाघाट जिले ने 87.56 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

जल गंगा संवर्धन अभियान में खेत-तालाब के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य वाले जिले को पुरस्कार देने के लिए ए तथा बी दो श्रेणियां बनाई गई थी। ए श्रेणी में 4 या उससे कम जनपदों को शामिल किया गया था, जबकि बी श्रेणी में 5 या उससे अधिक जनपदों को शामिल किया गया था। शुक्रवार को जारी सूची में ए श्रेणी जिसमें 4 या उससे कम जनपद है, उसमें अनूपपुर जिला व बी श्रेणी जिसमें 5 या इससे अधिक जनपद है, उसमें बालाघाट जिले ने अपना स्थान बनाया है।

जल गंगा संवर्धन अभियान में खेत-तालाब के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य वाली जनपद पंचायतों को विकासंखड स्तर पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। विकासखंड स्तरीय पुरस्कार के लिए भी ए और बी श्रेणी निर्धारित की गई थी। ए श्रेणी में 70 या उससे कम ग्राम पंचायतों वाली जनपद पंचायतों को शामिल किया गया था, जबकि बी श्रेणी के लिए 71 या उससे अधिक ग्राम पंचायत वाली जनपदों को शामिल किया गया था। ए श्रेणी में 70 या उससे कम ग्राम पंचायतों वाली जनपद पंचायतों में बालाघाट जिले की बिरसा जनपद पंचायत ने अपना स्थान बनाया है। बी श्रेणी के लिए 71 या उससे अधिक ग्राम पंचायत वाली जनपद पंचायत में अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ की जनपद पंचायत ने अपनी जगह बनाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में बारिश के पानी को सहेजने व पुरानी जल संरचनाओं को नया जीवन देने के लिए 30 मार्च से 30 जून तीन माह तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से गुड़ी पड़वा पर की थी। अभियान का समापन खंडवा में हुआ है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तीन माह में प्रदेश में 84 हजार 930 से अधिक खेत-तालाब, एक हजार 283 अमृत सरोवर और एक लाख 4 हजार 294 से अधिक रिचार्ज पिट और 1,283 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है या निर्माणाधीन है। इनसे एक लाख 67 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी।

किसानों ने किया कमाल, 4.77 लाख हेक्टेयर में फल उद्यान तैयार

शासन और समाज के समन्वय से जल संरक्षण, जल स्त्रोतों के पुर्नजीवन और जन-जागरूकता को समर्पित 'जल गंगा संवर्धन अभियान' में प्रदेश के हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग विभाग ने भी महती भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल और प्रेरणा से 30 मार्च से प्रारंभ किए गए अभियान में हॉर्टिकल्चर अमले और किसानों की भागीदारी शानदार रही है। इस अभियान में डेढ़ लाख से अधिक किसानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

अभियान के अन्तर्गत जल के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में 812 'पानी चौपाल' का आयोजन किया गया है। इनमें एक लाख 21 हजार से अधिक किसान सम्मिलित हुए। यह 'पानी चौपाल' 'वन-वे' नहीं 'टू-वे' कम्यूनिकेशन पर केन्द्रित रही, जिनमें किसानों द्वारा अपने गांव, खेतों में बने प्राकृतिक स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर विचार रखे गए।

पानी चौपाल के माध्यम से किसानों को पौधरोपण के लिए समझाया गया कि कम से कम 2 से 3 आयु वर्ष के पौधों का ही रोपण किया जाए, इनके जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है। वर्तमान में प्रदेश की विभिन्न नर्सरियों में 25 लाख से अधिक जीवित पौधे है, जो इच्छुक किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को पानी के महत्व को समझाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पर ड्राप-मोर क्रॉप अभियान भी चलाया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान में 12 हजार 488 हेक्टेयर क्षेत्र में इस पद्धति से सिंचाई के लिए लगभग 27 हजार कृषकों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जो एक उपलब्धि है। जल गंगा संवर्धन अभियान में 5000 हेक्टेयर में फलदार पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 25 जून तक प्रदेश में 6231 कृषकों द्वारा 3998 हेक्टेयर में फलदार पौध-रोपण कराया गया है। इनमें आम, अमरूद, नीबू, आंवला जैसे पौधों की प्रचुरता है। अभियान के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदेश में कितने क्षेत्र में कौन से फल उद्यान हैं। उनका आंकलन करना, फिर उत्पादन की मांग, क्षेत्र के आधार पर उसके विक्रय, फूड प्रोसेसिंग प्लान करना, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करना रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 4.77 लाख हेक्टेयर में फल उद्यान है। इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्र में संतरा 1 लाख 31 हजार 386 हेक्टेयर, आम 66 हजार 748 हेक्टेयर, अमरूद 57 हजार 81 हेक्टेयर, आंवला 32 हजार 455 हेक्टेयर, नीबू 28 हजार 290 हेक्टेयर, बेर 13 हजार 553 हेक्टेयर, कटहल 9306 हेक्टेयर, केला 34 हजार 864 हेक्टेयर, पपीता 14 हजार 352 हेक्टेयर और 89 हजार 241 हेक्टेयर क्षेत्र में अन्य फलों का उत्पादन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर उत्पादित फलों को बेहतर मार्केट मुहैया कराने के लिए आयोजित किए जा रहे, कृषि उद्यम समागम में आने वाले इन्वेस्टर्स को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर में आयोजित समागम में मध्यप्रदेश के संतना और केले की ब्रांडिंग करने पर विशेष जोर दिया। इन प्रयासों से प्रदेश के किसानों में नए उत्साह का संचार हो रहा है इसके बेहतर परिणाम शीघ्र ही धरातल पर परिलक्षित होने लगेंगे।

भोपाल में 'सांप' के शेप वाला पुल, मोड़ के तुरंत बाद आने वाले डिवाइडर से टकरा रही गाड़ियां!

सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल

भोपाल में 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ब्रिज के बाद अब राजधानी के ही एक और पुल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। महज 8 घंटे में हुए दो हादसों ने भोपाल के ही सुभाष नगर आरओबी के डिजाइन की खामी को सामने ला दिया है। हादसों से जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। भोपाल के सुभाष नगर में करीब 40 करोड़ की लागत से बने इस आरओबी को शुरू हुए दो साल हो चुके हैं लेकिन इसकी डिजाइन को लेकर जो शंकाए तब उठ रही थी वो अब हादसों के रूप में सामने आ रही है। इस पुल का डिजाइन सांप की तरह है।

सर्पाकार डिजाइन वाला यह पुल तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाज लगाना आसान है। इसी पुल पर मोड़ के बाद आने वाला रोड डिवाइडर किसी खतरे से कम नहीं है। इस डिवाइडर से टकरा कर एक गाड़ी हवा में उछल कर पलट जाती है तो दूसरी स्कूल वैन टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाती है। भोपाल के मैदा मिल से प्रभात पेट्रोल पंप तक जाने के लिए या फिर भोपाल रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए यह पुल समय की बचत और ट्रैफिक जाम के लिहाज से बेहद ही जरूरी है लेकिन इसकी डिजाइन की खामियां इस पुल की खासियत पर भारी पड़ रही है। पुल पर मैदा मिल तरफ उतरने के लिए रेलवे ट्रैक के उपर एक टर्न है और जैसे ही मोड़ खत्म होता है वैसे ही डिवाइडर शुरू हो जाता है। मोड़ के बाद अचानक से डिवाइडर आने से हादसे हो रहे है। डिवाइडर की उंचाई भी छोटी है जिससे कई बार यह दिखता भी नहीं है। बोर्ड ऑफिस से प्रभात पेट्रोल पंप जाने के लिए इस पुल पर चढ़ने के लिए जिंसी चौराहे की तरफ से आ रहे ट्रैफिक को क्रॉस करना होता है। लेकिन यहां लगा सिग्नल कभी काम करता है और कभी नहीं इससे जिंसी की तरफ से आ रहा ट्रैफिक और पुल पर चढ़ने वाला ट्रैफिक में टकराव का खतरा बना रहता है। बोर्ड ऑफिस की तरफ से आने वाले वाहन चालक को पहले दाएं मुड़कर पुल पर चढ़ना होता है और इसके तुरंत बाद उसे बाएं मुड़ना पड़ता है।इसके कुछ ही सेकंड बाद उसे फिर दाएं मुड़ना होता है और अगले ही पल उसे बाएं मुड़ना होता है । यानि कुछ ही सेकंड के भीतर उसे चार बार मुड़ना होता है। सिविल इंजिनियर भी इस तरह के पुल की डिजाइन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एम टेक कर चुके ब्रिज एक्सपर्ट प्रखर पगारिया ने बताया कि सर्पाकार आकार के पुल बनने ही नहीं चाहिए लेकिन कई बार जगह की कमी के चलते बना दिया जाता है लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा सुपरविजन रखना होता है क्योंकि एंगल का ध्यान नहीं रखा गया या बीच में डिवाइडर आ गया तो इससे हादसे हो सकते हैं जैसे रात में कोई आ रहा है तो वो टक्कर मार सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से इस पुल पर कम समय में 4 टर्न आते हैं वो बहुत घातक है क्योंकि इससे गाड़ी चलाने वाले को प्रतिक्रिया देने में बेहद कम समय मिलता है। बहरहाल, पुल पर फिलहाल जो हादसे हुए हैं उसमें गनीमत रही कि फिलहाल जान का नुकसान नहीं हुआ लेकिन आगे ऐसे हादसे दोबारा ना हो और किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े इसके लिए सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

रतलाम में हायर सेकंडरी स्कूल मैदान में सड़ रही हैं सैकड़ों साइकिलें

सच संवाददाता ॥ रतलाम

सैलाना में स्कूली बच्चों को वितरित की जाने वाली 100 से अधिक साइकिल हायर सेकंडरी स्कूल के खुले मैदान में खड़ी है। यह साइकिल ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल पढ़ने आने वाले छात्र और छात्राओं को वितरित की जानी थी। लेकिन शिक्षा विभाग और ठेकेदार की रस्साकशी के चलते बीते एक महीने से साइकिल भीग रही है।ठेकेदार ने बताया कि उनके द्वारा सभी साइकिलों को फिट कर वितरण के लिए तैयार कर दिया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक हैंडओवर नहीं लिया है। वहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि साइकिल की गुणवत्ता चेक करने के बाद भोपाल से निर्देश मिलने पर ही साइकिल का वितरण हो सकेगा। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किलोमीटर दूर से शासकीय स्कूलों में पढ़ने आने वाले छात्रों को सत्र की शुरुआत में साइकिल वितरित की जाती है। लेकिन इस बार स्कूल शुरू हुए 15 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों को साइकिलें वितरित नहीं की गई। सैलाना स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में ही करीब 400 साइकिल एक महीने से पड़ी है। मामले को तूल पकड़ता देख कुछ साइकिलों को स्कूल की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, हालांकि अभी भी सैकड़ों साइकिल कीचड़ में पड़ी हैं।खुले आसमान में खड़ी साइकिल पर ठेकेदार द्वारा बरसाती ढककर खानापूर्ति जरूर कर दी है। लेकिन जंग खा रही इन साइकिलों की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और साइकिल सप्लाई करने वाली कंपनी नहीं ले रही है। साइकिल सप्लाई करने वाली कंपनी एवन साइकिल के इंचार्ज ठेकेदार शकील अंसारी ने कहा,स्कूल का काम साइकिल को लाकर फिटिंग करने के बाद शिक्षा विभाग के सुपुर्द करना था। उन्होंने आगे कहा, लगभग 20 दिन पहले ही सभी साइकिलों की फिटिंग का कार्य पूर्ण कर दिया है। साइकिल को चलाकर चेक भी करवा दिया है। लेकिन शिक्षा विभाग वाले साइकिल नहीं ले रहे हैं।वहीं, इस पूरे मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी संजय नामदेव ने कहा,इस मामले में भोपाल से निर्देश मिलने के बाद ही साइकिल वितरण हो सकेगा।बहरहाल साइकिल सप्लाई करने वाले ठेकेदार और विकासखंड शिक्षा अधिकारी के बीच चल रही खींचतान का नतीजा उन छात्रों को भुगतना पड़ेगा। जिन्हें बारिश में करीब एक महीना भीगने के बाद साइकिल दी जाएगी।

बगैर बसाहट वाले रुट पर मेट्रो का संचालन यात्रियों का टोटा

इंदौर। इंदौर में मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की संख्या तेजी से घट गई। एक माह पहले जब इंदौर में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ था तो अधिकतम 25 हजार तक एक दिन में यात्रियों ने सफर किया था, लेकिन अब यात्रियों की संख्या 500 तक सिमट गई है। इस कारण मेट्रो के संचालन की लागत भी नहीं निकल पा रही है,जबकि मेट्रो के संचालन और स्टेशन पर 300 से ज्यादा कर्मचारियों का स्टॉफ रखा गया है। सुपर कॉरिडोर पर सात किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो ट्रेन का संचालन हो रहा है। मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने पहले सप्ताह में सफर मुफ्त रखा तो डेढ़ लाख से ज्यादा यात्रियों ने उसमें सफर किया, लेकिन जब टिकट लगने लगे तो यात्रियों की संख्या घट गई।दरअसल शहरवासी मेट्रो को देखने के लिए उसमे सफर कर रहे थे। अभी जिस हिस्से में मेट्रो का संचालन हो रहा है वहां न तो बसाहट है और न ही कोई औद्योगिक क्षेत्र। इस कारण वहां मेट्रो को वास्तविक यात्री नहीं मिल रहे है। अभी भी लोग जरुरत के बजाए शौकिया तौर पर मेट्रा के सफर का आनंद लेने जा रहे है। यात्री घटने के कारण मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने मेट्रो ट्रेन के संचालन का समय समय बदला है। अब ट्रेन सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक चलती है। फेरे भी कम हो गए है। अब मेट्रो ट्रेन का न्यूनतम किराया 15 रुपये है। सुपर कॉरिडोर पर टीसीएस और इंफोसिस के बड़े कैम्पस हैं। उनमें काम करने वाले कर्मचारी भी एरोड्रम क्षेत्र, सुखलिया ग्राम या विजय नगर क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन मेट्रो के मौजूदा रूट में ये इलाके नहीं हैं। इस कारण इन कंपनियों के कर्मचारियों को भी मेट्रो ट्रेन का ठीक से फायदा नहीं मिल पाएगा। यदि मेट्रो ट्रेन गांधी नगर से विजय नगर तक संचालित होती है तो फिर यात्री बढ़ सकते हैं, क्योंकि गांधी नगर क्षेत्र के कई लोग काम के सिलसिले में विजय नगर या उससे आगे जाते हैं।

तीन साल बाद तुअर दाल के भाव में बड़ी गिरावट, मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही सरकार

तुअर दाल के दाम में बड़ी गिरावट एमएसपी पर खरीद रही सरकार

सच संवाददाता ॥ शहडोल

भारत में ज्यादातर घरों में अरहर की दाल हर दिन बनने वाले भोजन में से एक है। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का ये एक बड़ा आधार भी है। दाल फ्राई और दाल तड़का के शौकीन आपको जगह-जगह मिल जाएंगे। इसीलिए अरहर कितना भी महंगा क्यों न हो, थोड़ी ही सही लेकिन हर व्यक्ति खरीदता जरूर है। ऐसे में आम लोगों के लिए ये दाल कितना अहम है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब आम लोगों से जुड़ी खबर ही है, कि सालों बाद अरहर दाल के दाम 100 रुपए के आसपास आ चुके हैं। जो आम लोगों को राहत देने वाली खबर है।

दलहनी फसल अरहर के उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश भी अरहर का एक बड़ा उत्पादक राज्य है। यहां के दाल की भी अच्छी खासी डिमांड है। अरहर उत्पादन में देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक तो सबसे ज्यादा उत्पादन करते ही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी इस मामले में तीसरे नंबर पर है। हलांकि इसके अलावा भी कुछ राज्य ऐसे हैं। जहां अरहर दाल का उत्पादन किया जाता है।अरहर की खेती खरीफ सीजन से ही शुरू हो जाती है। ये ज्यादा दिन की फसल होती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंन्द्र सिंह बताते हैं कि लगभग जुलाई महीने से ही अरहर की फसल लगाना किसान शुरू कर देता है। अरहर 120 से 170 दिन की अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से फसल होती है। मार्च-अप्रैल तक की इसकी नई फसल आनी शुरू भी हो जाती है। प्रदेश में अरहर का रकबा भी बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अरहर दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार इसे एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना भी शुरू कर चुकी है। मौजूदा साल सरकार ने 7550 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अरहर के फसल की खरीदी की है। अन्य दलहनी फसलों के एमएसपी की बात करें तो मसूर की एमएसपी 6700 रुपए, मूंग की एमएसपी 8682 रुपए, चना की एमएसपी 5650 रुपए और उड़द की एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल थी।

सालों बाद अरहर दाल हुआ है सस्ता

अरहर दाल जिसे तुअर दाल, राहर दाल के नाम से भी जाना जाता है। साल 2022 में इसके दाम 100 रुपए से लेकर 110 रुपए तक आये थे। फिर उसके बाद अरहर दाल के दाम कुछ इस कदर बढ़े कि वो 200 रुपए तक पहुंच गया था। लंबे समय तक लोगों को अरहर दाल खाने के लिए महंगाई की मार झेलनी पड़ रही थी, लेकिन 3 साल बाद ही सही एक बार फिर से अरहर दाल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है।अब वर्तमान में अरहर दाल की कीमत पहले से बहुत कम है। अलग-अलग क्वालिटी में अरहर दाल 80 रुपए से लेकर के 110 रुपए किलो तक बाजार में बिक रहा है। शहडोल सूर्या मार्ट के शशांक जैन बताते हैं कि कई सालों बाद अरहर दाल के दाम इतने कम हुए हैं। इससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।किराना दुकान चलाने वाले अभिषेक गुप्ता बताते हैं कि अरहर दाल की घटती कीमतों से उपभोक्ताओं को लंबे वक्त बाद थोड़ी बहुत राहत मिली है। तुअर दाल खुले बाजार में 80 रुपए से लेकर के 110 रुपए तक ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से बिक रहे हैं। उड़द दाल की बात करें तो 90-100 रुपए के आसपास बिक रहा है। मसूर दाल लगभग 70-80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। चना दाल भी 80-90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। क्वालिटी के हिसाब से दाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कई सालों के बाद अरहर दाल के दाम घटे हैं। उसने सालों बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।

किचन के बजट पर राहत

महीने भर का राशन लेने गईं हाउस वाइफ पार्वती और पूजा तिवारी अरहर दाल के सस्ता होने पर खुश हैं। उनका कहना है कि थोड़ी ही सही दाल की महंगाई से राहत तो मिली। किचन के बजट में भी थोड़ी बहुत बचत होगी, क्योंकि तुअर दाल एक ऐसी चीज है। जिसे कितना भी महंगा क्यों न हो, खरीदना ही पड़ता है। घर में हर दिन खाने में इसे बनाना जरूरी भी होता है, क्योंकि इसे पौष्टिक आहार में से एक माना जाता है। इतने सालों तक अरहर दाल की कीमत आसमान छू रही थी, लेकिन मौजूदा साल आखिर ऐसा क्या हुआ जो अरहर दाल की कीमत पिछले तीन साल के बराबर आ चुकी है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, दलहन में अगले 4 सालों में आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के बीच अब बड़ी तादाद में दाल के आयात को प्राथमिकता दी जा रही है। जिससे दाल की कीमत में गिरावट आ रही है।विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी की जारी अधिसूचना के मुताबिक तुअर दाल के शुल्क मुक्त आयात की नीति 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। भारत में मूंग के अलावा सभी तरह की दाल अरहर, उड़द, मसूर, चना और पीली मटर का शुल्क मुक्त आयात जारी रखे हुए हैं। जिससे अरहर जैसे दालों की कीमत टूटी है। अब ये बात आपको थोड़ी असहज जरूर कर सकती है कि भारत दलहन फसलों के उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है। मतलब दलहन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन फिर भी विश्व का सबसे बड़ा आयातक भी भारत ही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत जितना भी उत्पादन दलहनी फसलों की करता है, वो उसकी जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, मतलब खपत ज्यादा है। इसलिए उसे दूसरे देशों से भी दाल आयात करनी पड़ती है।भारत दाल का बड़ा आयातक है और मौजूदा वित्त वर्ष भी भारत ने काफी तेजी से दाल को अलग-अलग देशों से आयात किया है। भारत में दाल के आयात की बात करें तो अरहर और उड़द दाल ज्यादातर अफ्रीकी देशों से किया जाता है। कुछ म्यांमार से भी करता है, जबकि चना, मटर और मसूर जैसे दालों का आयात ऑस्ट्रेलिया रूस और कनाडा जैसे देशों से करता है।

रेत माफियाओं ने नायब तहसीलदार को रौंदने का किया प्रयास

मैहर। मैहर के रामनगर थाना अंतर्गत कुबरी गांव में रेत माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है। अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे नायब तहसीलदार रोशनलाल रावत को रेत से लदे ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की गई। इस हमले में वे बाल-बाल बच गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नायब तहसीलदार रोशन लाल रावत कुबरी गांव में सीमांकन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें अवैध रूप से रेत से लदा एक ट्रैक्टर दिखाई दिया। जब उन्होंने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, तो चालक ने जानबूझकर उन पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि तहसीलदार समय रहते पीछे हट गए और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। इस घटना में रावेंद्र नेपाली का नाम सामने आ रहा है, जो कथित रूप से अवैध रेत कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले मध्यप्रदेश के शहडोल क्षेत्र में एक पटवारी की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया था, जिसमें भी अवैध रेत खनन से जुड़ी आशंका जताई गई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और अवैध रेत कारोबार की जड़ें उजागर कर दी हैं। मैहर और शहडोल की सीमा पर लंबे समय से अवैध रेत खनन का कारोबार फल-फूल रहा है। प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन माफिया तत्व इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब अधिकारियों पर ही हमले करने से नहीं डरते।